

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 26 अगस्त, 2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों/नालियों के पुर्ननिर्माण हेतु अन्तिम किस्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 138/IV(2)-2014-14(सा0)14टी0सी0, दिनांक 28.02.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़ को नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों पर सी0सी0 इंटरलॉकिंग टाईल्स लगाने एवं नाले पुर्ननिर्माण कार्य हेतु ₹671.94 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में ₹100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्क्रम में प्रथम किस्त की धनराशि के उपयोगोपरान्त शासनादेश संख्या: 308/IV(2)-श0वि0-2015-14(सा0)14टी0सी0, दिनांक 03.03.2015 द्वारा ₹200.00 लाख, शासनादेश संख्या: 147/IV(2)-श0वि0-2016-14(सा0)14, दिनांक 25.01.2016 द्वारा ₹124.00 लाख एवं शासनादेश संख्या: 462/IV(2)-श0वि0-2016-14(सा0)14, दिनांक 18.03.2016 द्वारा ₹124.00 लाख अवमुक्त की गयी, इस प्रकार वर्तमान तक कुल ₹548.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- उपरोक्त के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़ के पत्रांक- 410/एन.पी./3-निर्माण/2016-17, दिनांक 18.07.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़ को प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत लागत रु. 671.94 लाख में न्यूनतम निविदा के सापेक्ष हुयी बचत ₹2.14 लाख को समायोजित करने के पश्चात अवशेष धनराशि ₹123.94 लाख के सापेक्ष ₹121.80 लाख (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- I. उक्त धनराशि ₹121.80 लाख (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख अस्सी हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़ को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- II. अवमुक्त की जा रही धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।
- III. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- IV. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- V. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
- VI. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना में नहीं किया जा सकता।

- VII. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृति से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- VIII. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- IX. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
- X. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- XI. इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- XII. धनराशि का दिनांक 31-3-2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूपों पर), फोटोग्राफ्स सहित शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत- 191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/xxviii(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेंट आई डी-S. 1608/3-0723 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्बाल)
सचिव।

संख्या-1466 (1)/IV(2)-श0वि0-2016, तददिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।